7

दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

3 सात बच्चों समेत 15 की मौत

5 धर्मेंद्र को प्रभार में झलक रहा अखिलेश का असमंजस
बदायूं का 'टिकट' लेकर कयासों को पंख लगा गए 'चाचा'

8 भारतीय क्रिकेट जगत में शोक की लहर

UPHIN51019 | वर्षः 01, अंकः 31 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 26 फरवरी, 2024

वाराणसी मेंप्रधानमंत्री द्वारा 13,100 करोड़ से अधिक की 35 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एवं अन्य वरिष्ठजनों के साथ सम्मिलित हुए।

बन रहा है नया गोरखपुर...

गरीबों को दिया छत, अमीर भी बना रहे आशियाना

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक नया गोरखपुर बन रहा है। हमारी सरकार ने सभी गरीबों को आवास दे दिया है। अब जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी जमीन और मकान उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक नया गोरखपुर बन रहा है। हमारी सरकार ने सभी गरीबों को आवास दे दिया है। अब जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी जमीन और मकान उपलब्ध करा रहे हैं। इसका फायदा गीडा की कंपनियों में नौकरी करने वालों को मिलेगा।

गीडा में परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद गोरखपुर में हो रहे बदलाव की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कालेसर से जंगल कौड़िया बाईपास बन जाने से पीपीगंज जाना आसान हो गया है। अब आधे घंटे में गीडा से पीपीगंज पहुंच जाएंगे। एम्स बन चुका है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन हो चुका है। खाद कारखाना शुरू हो चुका है।

चार-चार विश्वविद्यालय स्थापित हैं। पशु चिकित्सा महाविद्यालय को स्वीकृति दे दी है। इसे बाद में विश्वविद्यालय के रूप में

परिवर्तित किया जाएगा। सहजनवां में अटल आवासीय विद्यालय तो हरपुर में सर्वोदय विद्यालय बन चुका है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हुआ है और इस नए पन के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा।

हर श्रेणी के लोगों को मिलेगा प्लाट

सीएम ने कहा कि यूपी में भी 56 लाख गरीबों को मकान दिए जा चुके हैं। अब उनके लिए भी सोच रहे हैं जो अपना पैसा देकर आवास पाने के इच्छुक हैं। इस दिशा में गीडा और जीडीए ने कदम बढ़ाए हैं। गीडा की कालेसर आवासीय परियोजना में हर श्रेणी के लोगों के लिए आवास उपलब्ध हो सकेंगे। कालेसर आवासीय टाउनशिप 120 एकड़ में विकसित होगी। इसमें निम्न, मध्यम व उच्च आयवर्ग के लोगों की जरूरत के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े आकार के भूखंड उपलब्ध होंगे।

गीडा में सीख रहे हुनर, यही पाएंगे काम

सीएम ने नाइलिट के पहले बैच में नामांकन पाने वाले पांच छात्र-छात्राओं कोकिला साहनी, श्वेता गौतम, रौशनी, शनि कुमार व राहुल को नामांकन प्रमाण पत्र देने के बाद कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं के स्किल को बढ़ाने के लिए गीडा में नाइलिट के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण हो रहा है। पहले युवा नौकरी के लिए भटकते थे, अब यही ट्रेनिंग लेकर नौकरी हासिल कर लेंगे।

पहले गुमटी खोलने से डरते थे, आज करोड़ों का निवेश

सांसद रविकिशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश की छवि से निकाल कर मुख्यमंत्री ने सुरक्षित निवेश का प्रदेश बना दिया है। एक दौर था जब यहां लोग ठेला व गुमटी खोलने से पहले डरते थे। आज बड़ी-बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपये का निवेश हो रहा है।

सीबीएसई • नवंबर से ओपन बुक एग्जाम संभव

बोर्ड छोड़कर सभी परीक्षाएं किताबें खोलकर दे सकेंगे

नई दिल्ली |

सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र किताबें और नोट्स खोलकर परीक्षा दे सकेंगे। सूत्रों के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनएफसी) की सिफारिशों के तहत ओपन बुक एग्जाम (ओबीई) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी साल नवंबर-दिसंबर से शुरू किए जाने की संभावना है। हालांकि, ओपन बुक एग्जाम को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में लागू नहीं किया जाएगा।

एनएफसी का मानना है कि आरेबीई से छात्रों में परीक्षा के प्रति अनावश्यक तनाव और चिंताओं में कमी आएगी। इस बीच, सीबीएसई के निदेशक (एकेडमिक्स) डॉ. जोसेफ इमैनुएल का कहना है कि अभी ओबीई की स्टडी की जा रही है। इसके बाद तय होगा कि इसे कब और कैसे लागू किया जाएगा।

शुरू में कुछ स्कूलों में, बाद में देश भर में लागू होगा

सूत्रों के अनुसार, पायलट प्रोजेक्ट में कुछ स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम होगा। सभी पक्षों द्वारा आकलन करने के बाद इसे देशभर में लागू किया जाएगा।

- **9वीं-10वीं कक्षा में:** गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय में
- **11वीं-12वीं में:** अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के विषय में

दुनिया के कई प्रमुख देशों में ओपन बुक एग्जाम

- **यूरोपः** नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के स्कूलों में
- **अमेरिकाः** लॉ कॉलेज और एडवांस्ड प्लेसमेंट एग्जाम
- **जर्मनीः** इंजीनियरिंग के कोर्स
- **ऑस्ट्रेलियाः** मेडिकल की परीक्षाएं
- **ब्रिटेनः** इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स

डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र में कराया बेटी का दाखिला, आम बच्चों संग खेलती-पढ़ती है मासूम

बरेली। उत्तर प्रदेश में हाथरस के बाद अब बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। शुक्रवार को आम बच्चों के साथ खेलती मासूम बच्ची की तस्वीर सामने आई तो चर्चा शुरू हो गई।

बरेली के डीएम रविंद्र कुमार की बेटी का कांधरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए दाखिला कराया गया है। वह हम उम्र बच्चों के साथ खेलते और पढ़ते देखी गई तो उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। मासूम बच्ची की तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा। शहर में लोग डीएम के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा भी अपने दो साल के बेटे का एडमीशन आंगनबाड़ी में करा चुकी हैं। अब बरेली के डीएम ने मिसाल कायम की है। डीएम की यह पहल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सबक भी है। लोगों का कहना कि ये ऐसा दौर है जब सरकारी अधिकारी और अमीर लोग बच्चों को क्रेच और बड़े महंगे पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद डीएम ने बेटी को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत करवाकर मिसाल देने लायक काम किया है। इससे अन्य लोग भी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक भेजने के लिए प्रेरित होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों के इंतजाम सुधर सकते हैं। डीएम का ध्यान भी इन केंद्रों पर रहेगा।

जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनका देशी-विदेशी सैलानियों ने भरपूर आनंद लिया। प्रतियोगिताओं में विदेशी मेहमानों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

सम्पादकीय

लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा में भारत पाक

यह गजब संयोग है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस वक्त लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा से एक साथ गुजर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र की सुदीर्घ परंपरा रही है और पाकिस्तान लोकतंत्र के लिए संघर्ष करता आया है, यह दोनों देशों के बीच का बुनियादी फर्क है। यह गजब संयोग है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस वक्त लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा से एक साथ गुजर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र की सुदीर्घ परंपरा रही है और पाकिस्तान लोकतंत्र के लिए संघर्ष करता आया है, यह दोनों देशों के बीच का बुनियादी फर्क है। लेकिन दोनों देशों में एक बड़ी समानता ये है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए पाकिस्तान में भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। पहले इस चुनाव को केवल इस वजह से टाला गया कि पीठासीन अधिकारी बीमार थे। इसके बाद 30 जनवरी को जब चुनाव हुए तो आप और कांग्रेस का गठबंधन हार गया, जबकि भाजपा को आसान जीत मिल गई। इस चुनाव में आठ मतपत्रों को खारिज किया गया था और आप ने आरोप लगाए थे कि रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने ही मतपत्रों पर निशान बनाए थे।

उनका एक वीडियो फुटेज भी सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया था और सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने आठ मतपत्रों पर निशान लगाए थे। इसके बाद मंगलवार को अदालत ने मतपत्रों की फिर से गिनती के आदेश दिए हैं, इसमें खारिज किए सभी आठ मतपत्र भी शामिल थे, जिससे आप के कुलदीप कुमार मेयर घोषित हो गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव देश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से बहुत छोटा है। यहां पर विपक्ष ने हिम्मत नहीं हारी और इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखी, तो सच सामने आ गया। लेकिन इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों पर प्रश्नचिह्न तो लग ही गए हैं। और सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इस बात पर है कि क्या सत्ता के दबाव में स्वतंत्र संस्थाओं और अधिकारियों को बेईमानी करने दी जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान में हुए चुनाव में भी ऐसी ही बेईमानी हुई, लेकिन वहां एक अधिकारी ने सामने आकर अपनी बेईमानी न केवल कबूल की है, बल्कि खुद के लिए सजा की मांग भी कर दी।

पाकिस्तान में आम चुनाव हुए 10 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लोगों ने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी से ज्यादा वोट हासिल किए। फिर भी पीटीआई सरकार नहीं बना सकी, न ही अब तक नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कोई समझौता कर पाए हैं। इस बीच चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे थे और कहा गया था कि जीते हुए कई निर्दलीय प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित किया गया है। इससे पहले कि इस मामले की कोई जांच होती और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिलती, रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमने 13 ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट्स जो 70 से 80 हजार वोटों से आगे चल रहे थे, उन्हें धांधली कर हरवा दिया। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि वो इस वजह से सो नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने 'देश की पीठ में छुरा घोंपा हैय्। मैंने जो अन्याय किया है उसके लिए मुझे दंडित किया जाना चाहिए और इस अन्याय में शामिल अन्य लोगों को भी सजा होनी चाहिए। कमिश्नर चट्ठा ने यह भी कहा कि वे 1971 वाला दौर फिर नहीं देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि 1971 में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, क्योंकि तब भी शेख मुजीबुर्रहमान को चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान की सैन्य हुकूमत सत्ता सौंपना नहीं चाहती थी। इसके बाद जो कुछ हुआ, उस इतिहास से सब वाकिफ हैं।

पाकिस्तान का न्यायतंत्र, सैन्य तंत्र और सत्ता पर काबिज होने की इच्छा लिए राजनेता भले इस खूनी इतिहास से कोई सबक न लेना चाहें, लेकिन कमिश्नर चट्ठा ने एक रास्ता उन लोगों को दिखा दिया है, जो ईमानदारी के साथ लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं। यह याद रखना चाहिए कि आजादी के 75–76 बरसों में पाकिस्तान लोकतंत्र के लिए तरसता रहा है, सैन्य तानाशाही ने वहां लोकतंत्र की जड़ों को बार–बार कुचला और दूरी ओर धार्मिक कट्टरता से लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा गया। हालांकि वहां की अवाम इसके बावजूद लोकतंत्र की सत्ता स्थापित करने के लिए जूझती रही, उसने धर्म और सेना की सत्ता के आगे अपने जमीर का समर्पण नहीं किया। दूसरी ओर भारत ने आजादी के साथ ही लोकतंत्र का पौधा रोपा और 7 दशकों में इसे विशाल लहलहाते वृक्ष में तब्दील होते देखा। अफसोस इस बात का है कि अब अमृतकाल के नाम पर इस घने और मजबूत दरख्त की जड़ों में धर्मांधता और अधिनायकवाद का म–ा डाला जा रहा है। चंडीगढ़ के बाद बेईमानी के और नए गढ़ तैयार किए जा रहे हैं, जहां चुनाव प्रक्रिया से खिलवाड़ कर सत्ता की राह बनाई जा सके। कपट और धूर्तता से भरे इस रास्ते को तभी बंद किया जा सकता है जब प्रशासनिक ईमानदारी दिखाई जाए। जो काम रावलपिंडी में कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने किया है, क्या भारत के अधिकारी देश सेवा का वही जज्बा दिखा सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है।

मोदी के रामराज्य में सुदामा के चावल पर पीआईएल

सरकार से कामों से न्याय–अन्याय होने की मुहर लगाने का काम कोर्ट का होता है। संविधान में यही व्यवस्था है। न्यायालयों के सामने जवाब देने का काम सरकार का होता है। उसे न्यायपालिका में अपनी बात रखनी होती है। फैसला नापसंद होने पर भी उसे सर माथे पर लेना पड़ता है और कोर्ट द्वारा बतलाई गई खामियों को दूर करना होता है। भारत लोकतंत्र की जननी' है– यह कहने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार को कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास करते हुए नये तरीके से न्यायपालिका पर हमला बोल दिया है, जो बतलाता है कि वे सरकार के खिलाफ आ रहे अदालती फैसलों से खासे परेशान चल रहे हैं। उनकी परेशानी स्वाभाविक तो है लेकिन किसी भी देश के कार्यपालिका प्रमुख द्वारा ऐसी टिप्पणी न तो वांछनीय है और न ही शोभनीय। उन्हें अगर न्यायपालिका से किसी तरह की शिकायत है तो उन्हें यह द्वंद्व कोर्ट के भीतर ही निपटाना चाहिये। उस लड़ाई को इस प्रकार से किसी सार्वजनिक सभा तक ले जाना उचित नहीं। वैसे मोदी का गुस्सा इस लिहाज से जायज है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई फैसले केन्द्र सरकार के विरूद्ध तो आये ही हैं, निकट भविष्य में और भी सम्भावित हैं।

समारोह में मौजूद कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस से निकाले गये प्रमोद कृष्णम को सम्बोधित करते हुए मोदी ने तंज कसा कि 'यह तो अच्छा हुआ जो आपने (कृष्णम) केवल अपनी भावनाएं ही व्यक्त कीं। भावनाओं के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया वरना यह ऐसा समय चल रहा है कि अगर आज कृष्ण होते और सुदामा उन्हें चावल की पोटली भेंट करते तो कोई उसका वीडियो बनाता और पीआईएल (जनहित याचिका) दायर कर देता कि पोटली में क्या है।' मोदी के गुस्से का सबसे ताजा कारण निश्चित ही हाल का वह निर्णय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने मोदी सरकार द्वारा 2017–18 में लाये गये इलेक्टोरल (चुनावी) बॉड्स को 'असंवैधानिक, नागरिक अधिकारों का हनन और सूचना के अधिकार का उल्लंघन' बतलाया है। मोदी इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते कि जनता को कुछ बताया जाये। वे ऐसे हर नियम से खुद व उनकी सरकार को दूर कर देते हैं जिसमें जनता को जवाब देना पड़े। इसलिये वे मीडिया से बात नहीं करते, खुली परिचर्चाओं में हिस्सा नहीं लेते, कोई सवाल नहीं लेते। पत्रकार हों भी तो उनके अपने गोद लिये हुए अथवा अक्षय कुमार या प्रसून जोशी जैसे सिनेमा कलाकार–गीतकार हों जो उनसे पहले से दिये गये प्रश्नों के आधार पर आम चूसने के तरीकों और 18–18 घंटे काम करने के बावजूद न थकने का कारण जानना चाहते हैं। ऐसे प्रायोजित सवालों के उत्तरों पर कुर्बान होने वाला उनके प्रशंसकों व समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है, तो मोदी को अगर खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सम्राट होने की गलतफहमी हो जाये, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिये। यही कारण है कि देश में लोकतंत्र का आग्रह ही नहीं बल्कि शर्त मढ़ने वाला ऐतिहासिक संसद भवन उन्हें खाने को दौड़ता है। इसलिये वे उसे बन्द कर 'सेन्ट्रल विस्टा' बनवाते हैं, नये–नये परिधान पहनकर उसमें होने वाली कथित चर्चाओं में गेस्ट एपीयेरेंस देते हैं, विपक्ष को अपमानित करते हैं, 'पहले भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम न होने' का दुखड़ा सुनाते हैं। मोदी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं राजतंत्र में है इसलिये वे नये भवन में राजदण्ड का प्रतीक सेंगोल स्थापित करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में धर्म के लिये कोई जगह नहीं है इसलिये वे इसे राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। इससे धर्म की जगह बनती है। वैसे भी जनहित के काम करने के बनिस्बत धर्म के बल पर सरकार चलाना आसान होता है। जनता को राजतंत्र प्रणाली के पक्ष में सोचने व ढालने का एक और बड़ा फायदा मोदी जैसे राष्ट्राध्यक्षों को यह मिलता है कि विपक्ष जैसे तत्व से देश को मुक्त करने की अवधारणा बलवती होती है तथा (दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से) यह भी जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है कि राजा की आलोचना नहीं की जा सकती। इसीलिये जब मोदी कहते हैं कि उन्हें 'विपक्ष गालियां देता है', तो उनका इशारा सरकार की आलोचना करने या सवाल करने से होता है।

लोकतंत्र को छोड़कर राजतांत्रिक शासन प्रणाली में देश विश्वास करे या न करे, मोदी करते हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी करती है, मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और उनके समर्थक तो करते ही हैं। इसलिये वे यह नहीं जानते; और जानते भी हैं तो मानते नहीं, कि लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन का कामकाज शक्ति पृथक्करण के आधार पर चलता है। सरकार से कामों से न्याय–अन्याय होने की मुहर लगाने का काम कोर्ट का होता है। संविधान में यही व्यवस्था है। न्यायालयों के सामने जवाब देने का काम सरकार का होता है। उसे न्यायपालिका में अपनी बात रखनी होती है। फैसला नापसंद होने पर भी उसे सर माथे पर लेना पड़ता है और कोर्ट द्वारा बतलाई गई खामियों को दूर करना होता है।

संभल में मोदी का जो गुस्सा न्यायपालिका पर उतरा है, वह इसलिये कि उनकी सरकार को कई मामलों में कोर्ट की फटकारें सुननी पड़ी हैं। बहुत पीछे न जायें तो अनेक हालिया मामलों में केन्द्र सरकार के खिलाफ आये कई निर्णय मोदी को व्यथित करने के लिये काफी हैं। मणिपुर के मामले ने तो मोदी को घुटनों पर ला दिया था। पिछले साल के मई महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वहां की दो कुकी महिलाओं के साथ दो माह पहले हुए अमानवीय बर्ताव की ऐसी तस्वीरें थीं जिनसे देश ही नहीं पूरी दुनिया दहल गयी थी। सवाल खड़े होने लाजिमी थे। कई देशों की संसद में भी इस पर चर्चा हुई थी। यहां तक कि मोदी को इस मामले पर मुंह खोलना पड़ा था जिनकी सरकार ने (केन्द्र व राज्य की) इसे दबाये रखा था। नये संसद भवन के पहले सत्र के दिन तथा उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान संक्षिप्त ही सही, परन्तु मोदी को बयान देने पड़े थे। मोदी की परेशानियां यहीं तक नहीं रूकीं। जिन मोदी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री तथा बाद में पीएम के रूप में अपने (व साथियों के भी) पक्ष में कई अदालती फैसले पाए थे, डीवाई चंद्रचूड़ के आने के बाद अड़चन में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय सरकार के खिलाफ दिये हैं– वे भी तल्ख टिप्पणियों के साथ। मणिपुर में कहा कि 'यदि सरकार कुछ नहीं करती तो कोर्ट अपने तरीके से कुछ करेगी', तो वहीं चुनावी बॉड्स को 'रिश्वतखोरी' बतलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के ईमानदारी के मुखौटे को उतार फेंका। ऐसे ही, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में हुई धांधली को उन्होंने 'लोकतंत्र की हत्या' बतलाकर भाजपा को निर्वस्त्र कर दिया। अपने उत्पादों के लिये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जब यह गुहार लगाने जाते हैं कि, 'सड़क यातायात जाम के कारण सुनवाई में विलम्ब से या न आने वाले वकीलों के मुवक्किलों के विरूद्ध निर्णय न दिये जायें', तो चन्द्रचूड़ यह कहकर उन्हें बैरंग लौटा देते हैं कि 'वे चिंता न करें, कोर्ट देख लेगी।'

केंद्र को अब पारदर्शी चुनावी फंडिंग प्रणाली पर काम करना चाहिए

भविष्य में चुनावों में धन के प्रभाव को रोकने के लिए, हमें दान, खर्च सीमा, सार्वजनिक धन और प्रकटीकरण के लिए नियमों की आवश्यकता है। सरकार चुनाव सुधार के विकल्प तलाश रही है। भविष्य में चुनावों में धन के प्रभाव को रोकने के लिए, हमें दान, खर्च सीमा, सार्वजनिक धन और प्रकटीकरण के लिए नियमों की आवश्यकता है। सरकार चुनाव सुधार के विकल्प तलाश रही है। हमारे पास कई रिपोर्टें हैं जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं, इसलिए हमें उन्हें फिर से देखने की जरूरत है। हमें फंडिंग में पारदर्शिता पर जोर देकर चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए बदलाव करने होंगे।

भारतीय चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लाखों मतदाता और अनेक राजनीतिक दल शामिल होते हैं। ये पार्टियां अपने अभियानों के वित्तपोषण के लिए व्यक्तियों और निगमों के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, क्योंकि फंडिंग महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान बहुत सारा काला धन भी घूमता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने राजनीति में अवैध धन का उपयोग रोकने का वायदा किया था। तीन साल बाद, 2017 में उन्होंने चुनावी बांड योजना पेश की, जिसके बारे में उनका दावा था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, कुछ लोगों ने गोपनीयता खंड और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को अदालत में चुनौती दी। पिछले हफ़्ते सर्वोच्च न्यायालय ने गुमनाम राजनीतिक चंदे को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले को भाजपा के लिए पचाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि 2018 से प्रभावी इस योजना से सत्तारूढ़ दल को सबसे अधिक फायदा हुआ है।शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि 'चुनावी बांड' नागरिकों के सरकारी जानकारी तक पहुंचने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और संविधान की धारा19(1)(ए) का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने खुले शासन के महत्व पर जोर दिया, 'मतदान के विकल्प का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।' सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक को इन बांडों को जारी करने से रोकने और भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला पांच जजों के समूह ने दिया। न्यायाधीशों ने जांच की कि क्या चुनावी बांड योजना ने संवैधानिक नियमों को तोड़ा है, मतदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से रोका है, दानदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करते हुए गुप्त दान की अनुमति दी है, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खतरे में डाला है?

पहले, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक का योगदान देने वाले दानदाताओं की पहचान का खुलासा करना आवश्यक था। हालांकि, चुनावी बांड राजनीतिक दलों को दानदाताओं की पहचान उजागर किये बिना प्राप्त धन की रिपोर्ट करने की अनुमति देते हैं। इन बॉन्ड्स की रेंज 1,000 से 10 करोड़ रुपये तक होती है।

लोगों को जानना चाहिए कि राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी है या नहीं। मुख्य आलोचनाओं में से एक यह है कि इन बांडों को खरीदते समय यह पता लगाना कठिन है कि पैसा कहां से आता है, जिससे धन के स्रोत की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

2017 से 2022 तक के एडीआर आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान निगमों द्वारा दान की गई कुल राशि 3,299.85 करोड़ रुपये थी। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला। चुनावी बांड के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को 406.45 करोड़ रुपये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 109.5 करोड़ रुपये और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को 49.7 करोड़ रुपये मिले।

एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजनीतिक योगदान के बारे में जानकारी छिपाना अनुचित है। करदाताओं को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को धन कहां से मिलता है। पारदर्शिता की कमी जवाबदेही पर सवाल उठाती है। करदाताओं का पैसा बांड छापने में खर्च होता है और एसबीआई को उनकी बिक्री से मुनाफा होता है। इसमें दावा किया गया है कि करदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को धन कहां से मिलता है। अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता जवाबदेही के बारे में संदेह पैदा करती है। करदाताओं के पैसे का उपयोग बांड मुद्रित करने के लिए किया जाता है, और उनकी बिक्री से एसबीआई के मुनाफे को अनुचित माना जाता है। जनता और विपक्षी दलों को इन दान के स्रोत के बारे में पता होना चाहिए, हालांकि सरकार एसबीआई से दाता विवरण प्राप्त कर सकती है।

संसद में, सरकार ने प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों और विपक्षी संसद सदस्यों की चेतावनियों की उपेक्षा की और चुनावी बांड योजना शुरू की। बांड विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। इससे पहले, कानून मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया था कि बांड योजना को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग और आरबीआई ने भी 2017 योजना के प्रावधानों का विरोध किया, लेकिन सरकार ने भाजपा के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया। चुनाव आयोग ने 2,858 राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया है, लेकिन केवल एक छोटा प्रतिशत, केवल 2.17प्रतिशत, वर्तमान में मान्यता प्राप्त हैं। कुछ पार्टियां कभी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकती हैं, जबकि अन्य मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं।

2019 के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को रिकॉर्ड तोड़ रकम मिली। चुनावी बांड के माध्यम से 2,760.20 करोड़ का गुमनाम चंदा आया। यह 2017–18 और 2018–19 में मिली सबसे ज्यादा रकम थी। 2017–18 से 2020–21 तक, 19 राजनीतिक दलों ने लगभग 6.5 हजार करोड़ रुपये के चुनावी बांड भुनाये। पिछले छह लोकसभा चुनावों में खर्च लगभग छह गुना बढ़ गया है जो 9,000 रुपये से बढ़कर 2019 में 55,000 करोड़ रुपये हो गया था। 2018 से मार्च 2022 तक भाजपा को 57 प्रतिशत चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ।

उम्मीद है कि सरकार पहले के अवसरों के विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब इसे अमल में लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दानकर्ता की गोपनीयता और पूर्वव्यापी खुलासे पर आपत्ति है। उनका दावा है कि अदालत का आदेश आगामी अप्रैल–मई चुनावों में भाजपा की संभावनाओं को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि उनका लक्ष्य पीएम मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करना है।

भविष्य में चुनावों में धन के प्रभाव को रोकने के लिए, हमें दान, खर्च सीमा, सार्वजनिक धन और प्रकटीकरण के लिए नियमों की आवश्यकता है। सरकार चुनाव सुधार के विकल्प तलाश रही है। हमारे पास कई रिपोर्टें हैं जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं, इसलिए हमें उन्हें फिर से देखने की जरूरत है। हमें फंडिंग में पारदर्शिता पर जोर देकर चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए बदलाव करने होंगे।

यूपी में बड़ा हादसाः कासगंज में तालाब में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली

सात बच्चों समेत 15 की मौत

कासगंज। यूपी के कासगंज जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर–ट्रॉली तालाब में गिर गई। हादसे में सात मासूम बच्चे और आठ महिलाओं की मौत हो गई। मौके पर चीख–पुकार मची हुई है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पटियाली–दरियावगंज मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। तालाब में जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। जिसमें ज्यादातर श्रद्धालु दब गए। इस हादसे में 15 से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है।

मृतकों में आठ महिलाएं और साथ बच्चे शामिल हैं। कई गंभीर घायल श्रद्धालुओं का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और कुछ को रेफर किया गया है। घटनास्थल से लेकर जिला अस्पताल तक अफरा तफरी का महौल बना हुआ है।

डीएम, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। परिवारों में चीत्कार मचा हुआ है।

मृतकों में एक एक परिवार के कई कई लोग शामिल हैं। प्रशासन के द्वारा अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। सीएमओ डॉ. राजीव अग्रवाल ने बताया कि सात बच्चे और आठ महिला पटियाली के सीएचसी पर मृतक घोषित किए गए हैं। एंबुलेंस से जो अन्य घायल जिला अस्पताल लाए गए हैं उनका परीक्षण चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। स्थिति अधिक गंभीर है।

वार्ड नहीं ट्रामा सेंटर में ही चलेगी मेडिसिन विभाग की इमरजेंसी सेवा

गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अब दो नहीं एक ही जगह इमरजेंसी सेवा चलेगी। ट्रामा एवं इमरजेंसी वार्ड में ही मेडिसिन विभाग की इमरजेंसी सेवा भी शिफ्ट कर दी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टरों की शिफ्टवार ड्यूटी भी लगने लगी है।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अब दो नहीं एक ही जगह इमरजेंसी सेवा चलेगी। ट्रामा एवं इमरजेंसी वार्ड में ही मेडिसिन विभाग की इमरजेंसी सेवा भी शिफ्ट कर दी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टरों की शिफ्टवार ड्यूटी भी लगने लगी है। डॉक्टरों की मौजूदगी की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों की होगी।

मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल से मरीजों को बेचने का मामला तूल पकड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने इसमें सुधार के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पहले ट्रामा सेंटर में सर्जरी, गायनी, आर्थो व एनेस्थीसिया की टीम रहती थी। मेडिसिन के रोगियों को पर्ची बनाकर सीधे 11 नंबर इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया जाता था।

ट्रामा सेंटर से मेडिसिन वार्ड के बीच में ही दलाल उन्हें गुमराह कर देते थे। इस पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अब ट्रामा एवं इमरजेंसी में ही मेडिसिन विभाग के भी डॉक्टर रहेंगे। उपचार शुरू होने के बाद रोगियों को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल आए मरीजों का उचित उपचार हो सके, इसके लिए डॉक्टरों की मौजूदगी पर निगरानी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार आर्या ने कहा कि हमने सुधार के लिए जो भी जरूरी प्रयास हैं, वह शुरू किए हैं। जल्द ही व्यवस्था में बदलाव दिखेगा।

मरीज–माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करेगी पुलिस...चलेगा अभियान

गोरखपुर। गोरखपुर पुलिस ने मरीज माफियाओं का नेटवर्क को ध्वस्त करने का फैसला किया है। डीआईजी ने रेंज के सभी एसपी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग से तालमेल कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मरीज माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, गोरखपुर की तर्ज पर पड़ोसी जिलों महराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में भी अभियान चलाएगी। इसके लिए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने रेंज के तीन अन्य जिलों के पुलिस कप्तान को पत्र भेजकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। पत्र में गोरखपुर में हुई कार्रवाई का जिक्र करने के साथ ही जांच का तरीका भी समझाया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस मुहिम को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएगी।

गोरखपुर में मरीज माफिया पर कार्रवाई होने के बाद आसपास के जिलों में भी हड़कंप मचा है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में भी कई ऐसे ही फर्जी तरीके से नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। बिना डॉक्टर के ही मरीज को भर्ती किया जाता है और फिर मरीज की जान जाने के बाद ही जानकारी दी जाती है।

डॉक्टर के नाम पर अस्पताल का पंजीकरण है, वह कभी आते ही नहीं। कई कस्बों में पंजीकरण न होने के बाद भी अस्पताल का बोर्ड लगाकर मरीजों को ठगा जा रहा है। डीआईजी ने इसका संज्ञान लेते हुए तीनों जिले के एसपी को संयुक्त टीम गठित कराने को कहा है, जिससे ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। मरीज व एंबुलेंस माफिया पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भी भेजी जाएगी।

गिरोह में शामिल आरोपी फरार, तलाश में दबिश

बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मरीज की खरीद–फरोख्त के मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अब नामजद आरोपी फरार हो गए हैं।

पुलिस की टीम रात के समय तलाश में घरों पर दबिश देने पहुंची तो आरोपी फरार मिले। तीन हॉस्पिटल के संचालक व एंबुलेंस माफिया के जेल जाने के बाद हड़कंप की स्थिति है। ईशु हॉस्पिटल की संचालक रेनू के अलावा मनोज निगम के न्यायालय में समर्पण करने की सूचना पर पुलिस ने वहां भी पहरा बैठा दिया है।

संदिग्ध अस्पतालों पर लगे ताले

पुलिस ने 10 संदिग्ध अस्पतालों की जांच शुरू की तो इसमें से कई पर ताला बंद मिला है। वहीं, सीएमओ दफ्तर भी कई डॉक्टर अब पहुंचने लगे है कि पुराने जगह पर उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है। अब उनका अस्पताल से नाता नहीं है। पुलिस ने इधर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है तो डीआईजी ने इसे देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज पुलिस को भी कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि रेंज के सभी जिले में मरीज माफिया पर कार्रवाई का निर्देश पुलिस को दिया गया है। गोरखपुर में हुई कार्रवाई में कई मामले सामने आए है। इसी तरह अन्य जिले में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाकर कार्रवाई को पत्र लिखा गया है।

तिवारी हाता में ईडी की टीम खंगाल रही थी दस्तावेज.. बाहर यही चर्चा–आई क्यों

गोरखपुर। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार स्थित पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा शाम छह बजे खत्म हो गया। सुबह 6 बजे से ही टीम पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी कर रही थी। तिवारी हाता में शुक्रवार सुबह ईडी की टीम के पहुंचने के बाद से शहर में हलचल शुरू हो गई। समर्थक गेट के बाहर जुटने लगे तो बाजार में हर ओर एक ही चर्चा थी–आखिर ईडी की टीम किसलिए आई है? पूर्व विधायक विनय शंकर और उनके परिवार को जानने वाले उनसे संपर्क साधने की कोशिश में थे, लेकिन उनके मोबाइल फोन पर बात नहीं हो पा रही थी।

सुबह दस बजते–बजते गेट के बाहर समर्थक जुटने लगे। कुछ की नजर हाता में बैठे पूर्व सांसद भीष्मशंकर तिवारी पर पड़ी। वह आराम से अखबार पढ़ते नजर आए। कई लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाता में कार्रवाई की चर्चा शहर के हर चौक–चौराहे पर हो रही थी। दोपहर करीब 12 बजे धर्मशाला चौक के पास ही चाय की दुकान पर खड़े लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। चाय की चुस्की के साथ सभी एक ही बात बोल रहे थे–अचानक ईडी की टीम क्यों आई है? इसे लेकर सबके अपने–अपने तर्क भी थे। तभी वहीं के रहने वाले अभिषेक तिवारी बोल पड़े– यह राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है तो विकास ने इसका विरोध किया। कहा–ईडी अपनी कार्रवाई करती है। जरूर कुछ तो होगा, तभी तो कार्रवाई की जा रही है। शहर के पुराने आरटीओ के पास चाय की दुकान पर कुछ इसी तरह की चर्चा लोगों के बीच सुनी गई। बातचीत में सभी अपने–अपने ढंग से ईडी की कार्रवाई की व्याख्या करते नजर आए। कोई इसे दबाव बनाने की कोशिश बता रहा था तो कोई बदनाम करने की।

इस बीच शाम छह बजे ईडी अपनी जांच–पड़ताल कर निकलने लगी तो सपा नेता और समर्थकों की भीड़ नारेबाजी करने लगी। कार्यकर्ता इसे दबाव बनाने की कार्रवाई बताकर हर कदम पर हाता का साथ देने का दम भरते नजर आए। इस बीच हाता में हलचल शाम के बाद बढ़ गई। गेट खुलने के बाद समर्थकों की भीड़ अंदर गई। पूर्व विधायक के बड़े भाई व पूर्व सांसद भीष्म शंकर ने समर्थकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव में दबाव बनाने के लिए ईडी को भेजा गया था। इतनी देर तक जांच के बाद भी टीम को कुछ हासिल नहीं हुआ है। वहीं, सूत्रों ने बताया कि ईडी के लखनऊ जोन के अधिकारी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी लेने गोरखपुर घर पर पहुंचे हैं। कंपनी सड़कों के निर्माण, टोल प्लाजा के संचालन और सरकारी अनुबंधों में काम करती है। समूह के मुख्य प्रवर्तक विनय शंकर तिवारी, रीता, तिवारी और अजीत पांडे हैं। यह बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा लगभग 750 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी है। यह धोखाधड़ी 2012 से 2016 की अवधि से संबंधित है।

आते–जाते रहे लोग, कई डटे भी रहे

हाता पर सुबह से ही समर्थक आते–जाते रहे। सब यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है और कब तक चलेगा। वहीं, कई ऐसे भी समर्थक थे, जो सुबह से ही डटे और वह ईडी के शाम में जाने के बाद ही अंदर गए, लेकिन बीच में हटे नहीं।

पुलिस को लौटा दी थी टीम

गोरखनाथ पुलिस भी जानकारी होने के बाद मदद के लिए गई थी, लेकिन अंदर मौजूद अर्द्धसैनिक बलों ने कोई जरूरत न होने की बात कहते हुए लौटा दिया। हालांकि, पुलिस अपने स्तर से शाम कार्रवाई होने के बाद तक सक्रिय रही। पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखी।

कारीगर के बाहर आते ही जुट गए लोग, तो कार से छोड़ा

ईडी की टीम के अंदर जाने के बाद अलमारी खोलने के लिए कारीगर की जरूरत थी।

इसके बाद लोकल पुलिस से संपर्क कर कोतवाली इलाके से एक कारीगर को लाया गया। गेट खुलते ही वह अंदर गया और आलमारी खोलने के बाद वह बाहर गया। बाहर आते ही उससे लोग अंदर हो रही कार्रवाई के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। इसकी जानकारी होने के बाद अंदर से एक कार आई और कारीगर को उसकी दुकान पर छोड़ दिया गया। ईडी के छापे की कार्रवाई की खबर सुनते ही समर्थक जुटने लगे। हालांकि, अंदर किसी से संपर्क करने की अनुमति किसी को नहीं है। सभी को फोन भी ईडी टीम ने जब्त कर लिए हैं। हाते की अंदर सिर्फ पूर्व मंत्री के बड़े बेटे पूर्व सांसद कुशल त्रिपाठी हैं और परिजन हैं। छोटे बेटे पूर्व विधायक विनय त्रिपाठी लखनऊ स्थित आवास पर हैं।

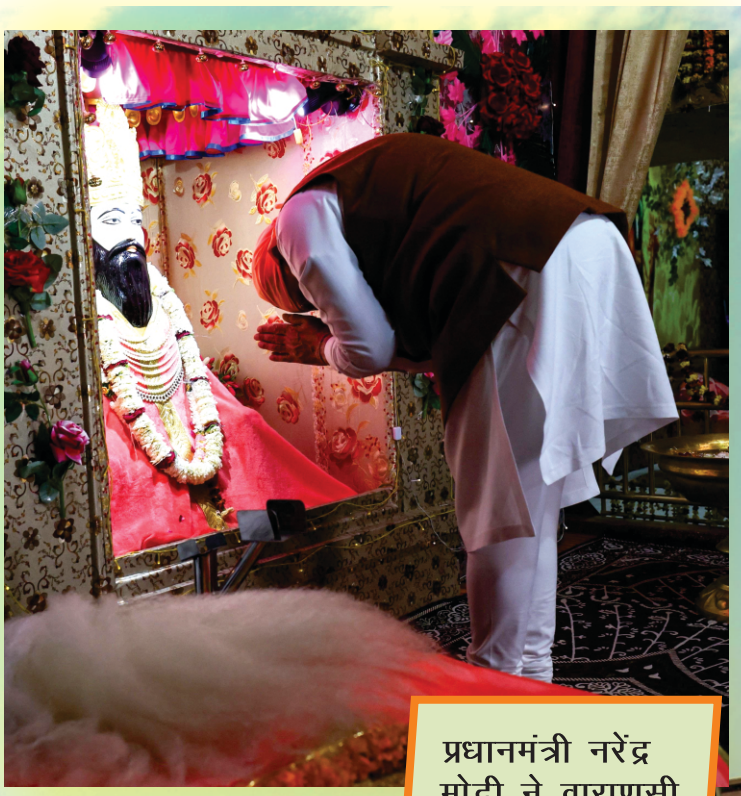

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।

पीएम मोदी ने देर रात अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

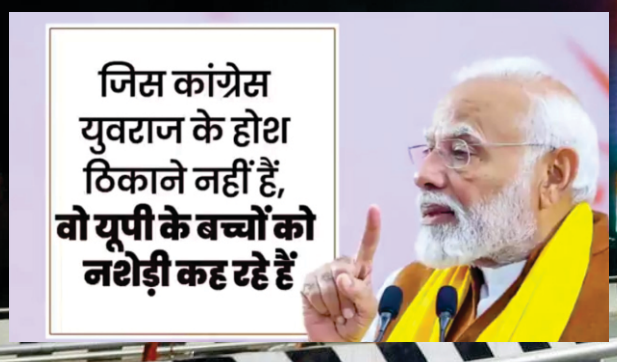

धर्मेंद्र को प्रभार में झलक रहा अखिलेश का असमंजस

बदायूं का 'टिकट' लेकर कयासों को पंख लगा गए 'चाचा'

लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट में भी भले ही जिले से अभी किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है लेकिन धर्मेंद्र यादव को कन्नौज के साथ आजमगढ़ का लोकसभा प्रभारी बनाए जाने से अब सर्वाधिक चर्चा यहल्ल की है। इसमें अखिलेश का असमंजमस साफ झलक रहा कि वह कौन सी सीट से खुद लड़ें।

आजमगढ़। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट में भी भले ही जिले से अभी किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन धर्मेंद्र यादव को कन्नौज के साथ आजमगढ़ का लोकसभा प्रभारी बनाए जाने से अब सर्वाधिक चर्चा यहीं की है। इसमें अखिलेश का असमंजमस साफ झलक रहा कि वह कौन सी सीट से खुद लड़ें। फागुनी बयार भले ही अब तक गर्माहट भरी अंगड़ाई न ले सकी हो, लेकिन आजमगढ़ की सियासी हवा रंगत में है। राजनीतिक रूप से समृद्ध रहे इस जनपद के मायने अलग हैं। आजमगढ़ की सियासत का पूर्वांचल पर खासा प्रभाव रहता है। यहां की दो सीटों में सदर भाजपा के पास है।

आजमगढ़ को माना जाता है सपा का गढ़

यहां से दिनेशलाल यादव निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में कांटे की टक्कर में हराया था। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता रहा है। इसमें उपचुनाव में भाजपा ने सेंध लगाई तो तमाम कारणों में से प्रत्याशी का अंतिम दौर में आना भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था।

अब इस बार पार्टी ने तेजी दिखाई जरूर, लेकिन धर्मेंद्र यादव को दो जगहों का प्रभार देने से यह साफ हो गया कि अखिलेश यादव अभी अपनी सीट को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं कर सके हैं। बहरहाल, जिले से सपा के कद्दावर नेता और विधायक शिवपाल यादव के आजमगढ़ से सर्वाधिक संभावना जताई जा रही थी। अब उनको बदायूं लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उपचुनाव में सपा प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र यादव पर निगाहें थीं, लेकिन उन्हें यहां और कन्नौज का प्रभारी बनाए जाने से अटकलों को पंख लग गए हैं।

क्या भाजपा से हार का बदला ले सकेगी सपा

लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी–जान से जुटे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) वोटबैंक को लक्ष्य बनाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे अधिक चर्चा यादव परिवार को लेकर है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए पूरा यादव कुनबा ताकत झोंकेगा। सियासी खेमे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आजमगढ़ से इस बार अखिलेश यादव खुद मैदान में होंगे।

पार्टी का निर्णय हर कार्यकर्ता को शिरोधार्य है। हम सभी लोग लगकर सीट को जीतकर ही रहेंगे प्रत्याशी कोई भी हो। जहां तक प्रभार की बात है तो उससे यह तर्क लगाना कि वह अब प्रत्याशी नहीं होंगे कतई उचित नहीं है। जल्द ही यहां की सीट पर भी निर्णय हो जाएगा। – अशोक यादव, सपा प्रवक्ता।

लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश को एक और बड़ा झटका

इधर सपा–कांग्रेस गठबंधन में बनी बात, उधर राष्ट्रीय सचिव ने दे दिया इस्तीफा

समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां पार्टी की कांग्रेस से सीटों के गठबंधन पर सहमति बनी वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी के बाद अब राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र लसह तोमर ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने इसका पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है।

संवाददाता, अलीगढ़। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां पार्टी की कांग्रेस से सीटों के गठबंधन पर सहमति बनी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी के बाद अब राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने इसका प्त्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। इस पत्र में इन्होंने कहा है कि उन्होंने अब तक की राजनीति पांच बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के साथ ही की है। अब वह सपा से अलग हो गए, ऐसे में उनके लिए भी पार्टी के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं हैं।

रियल स्टेट कारोबारी हैं योगेंद्र लसह

पार्टी में अल्पसंख्यकों के साथ ही सामान्य और पिछड़े वर्ग की अनदेखी हो रही है। योगेंद्र सिंह तोमर पश्चिमी यूपी के प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। अलीगढ़ के साथ ही नोएडा व बंदायू में इनका कारोबार है।

शहर के लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित जापान हाउस के पार्क व्यू रेजीडेंसी निवासी योगेंद्र सिंह तोमर बंदायू की गुन्नौर तहसील के मिठनपुर गांव के मूल निवासी हैं। रियल एस्टेट कारोबार में इनकी अलग पहचान है। यह पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं।

धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाने में था अहम योगदान

2014 में बंदायू लोकसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाने में अहम योगदान था। सामान्य वर्ग के साथ ही पिछड़े और अल्पसंख्यकों में इनकी गहरी पैठ है। समाज सेवा के लिए भी अलग पहचान है। ऐसे में पिछले दिनों समाजवादी पार्टी इनको राष्ट्रीय महासचिव पद पर नामित किया था, मगर बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के त्याग पत्र के बाद इनके भी समाजवादी पार्टी छोड़ने की अटकले लगाईं जा रही थीं।

इन्होंने अचानक से पार्टी से त्याग पत्र देने का एलान कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी में मुसलमानों के साथ ही सामान्य और पिछड़े वर्ग उपेक्षा से परेशान होकर राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के साथ इन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। कई साल से वह पूरी मेहनत से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मगर, अब पार्टी में मेहनती कार्यकर्ताओं को तवज्जों नहीं मिल रही है।

राज्यसभा न भेजने पर कार्यकर्ताओं में रोष

पूर्व केंद्रीय मंत्री के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई गई है। इसी के चलते अल्पसंख्यक समाज के साथ ही सेक्युलर नीति से सामान्य और पिछड़ों में अलग पहचान रखकर पार्टी को मजबूत करने वाले व्यक्ति ने भी पार्टी पद से त्याग पत्र दे दिया है। इतनी कर्मठता के बाद भी इन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। इससे जमीनी कार्यकर्ताओं में रोष है। सपा की पीडीए नाम की राजनीति भी अब दिखावा लगती है। कई बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्षत्रीय और ब्राह्मण हित में बात करने के प्रयास किए गए, मगर उन्होंने इस बात को सुनना ही पसंद नहीं किया। पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सम्मान नहीं हो रहा है। छुट भइये नेताओं के कहने पर प्रदेश में राज्य सभा सीटों का बंदरबांट किया गया है। जिन लोगों का जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें राज्य सभा भेजा है। इससे उनका मन काफी आहत है।

पूर्व सांसद मुनव्वर हसन व तबस्सुम की बेटी और विधायक नाहिद हसन की बहन हैं इकरा। अखिलेश यादव ने सपा के कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन को समाजवादी पाटी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी प्रत्याशी बनाया है। इकरा कुछ समय से राजनीति में सक्रिय हैं।

सपा: कैराना से इकरा

लंदन से पढ़ाई, पिता पूर्व सांसद-भाई विधायक

लंदन में पढ़ी हैं इकरा, विस चुनाव में संभाली थी कमान
अख्तर हसन कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे

संवाददाता, कैराना (शामली)। अपराध के कारण पलायन से देश–दुनिया में चर्चित कैराना संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन पुत्र भ्ंदको प्रत्याशी बनाया है। इकरा के दादा, पिता व मां सांसद रह चुकीं हैं। जबकि बड़ा भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक है। इकरा 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पांच हजार वोटों से हार चुकी है। वर्तमान में यहां से भाजपा के प्रदीप चौधरी सांसद हैं। गुर्जर जाति से आने वाले प्रदीप ने इकरा की मां और दो बार की सांसद सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हराकर चुनाव जीता था।

कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे अख्तर हसन

राजनीति में हसन परिवार के मुखिया अख्तर हसन ने नगरपालिका परिषद चुनाव में सभासद का चुनाव लड़ा और जीते थे। इसके बाद वह चेयरमैन और फिर कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे। अख्तर ने पुत्र मुनव्वर हसन को राजनीति में उतारा, जिन्होंने पश्चिमी यूपी के बड़े नेता के तौर पर छाप छोड़ी। उनके दिवंगत होने पर उनकी पत्नी तबस्सुम बेगम कैराना लोकसभा सीट से दो बार सांसद रहीं। तबस्सुम के बेटे नाहिद हसन कैराना विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं। इकरा हसन के रूप में परिवार की दूसरी महिला लोकसभा प्रत्याशी बनी है।

लंदन में पढ़ाई के दौरान सीएए का विरोध कर आईं थल सुरखयों में

27 वर्षीय इकरा की शुरुआती शिक्षा भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से की थी।

लेडी श्रीराम कालेज से ग्रेजुएशन किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की।

इंटरनेशनल ला एंड पालिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी आफ लंदन से किया था।

लंदन में सीएए का विरोध–प्रदर्शन कर सुर्खियों में आई थीं।

वह पढ़ाई पूरी कर 2021 में स्वदेश लौटी थीं। इसके बाद ही वह इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हुईं।

इकरा ने 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन पांच हजार वोटों से हार मिली

विधानसभा चुनाव में संभाली थी कमान

2022 के विधानसभा चुनाव से पहले विधायक नाहिद हसन जेल में थे। चुनाव में उनकी छोटी बहन इकरा ने ही चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली थी। भाई की जीत में बहन की मेहनत को ही माना जाता है।

नकुड़ और गंगोह बनेंगे निर्णायक

संसदीय क्षेत्र में सहारनपुर जनपद के नकुड़ और गंगोह विधानसभा क्षेत्र पूर्व के चुनाव से ही यहां के परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं। इस बार भी नकुड़ और गंगोह क्षेत्र में सैनी तथा गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगे। शामली जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र में कैराना, शामली और थानाभवन समेत सहारनपुर जनपद के दो विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर लगभग साढ़े पांच लाख मुस्लिम मतदाता हैं।

यूपी सरकार का दावा - सात साल में 12.80 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ के पार पहुंचा बैंकिंग व्यवसाय

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का कवरेज 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। 59 प्रतिशत सीडी रेशियो का लक्ष्य पूरा हो गया है अब अगले वर्ष में सीडी रेशियों का लक्ष्य 65 प्रतिशत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बैंकों का सीडी रेशियो (ऋण जमानुपात) 58.59 होने पर प्रसन्नता जताते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 65 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का कवरेज सभी 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद और ऊर्जावान युवा को ऋण के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में बैंकों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। ऋण मेलों का यह क्रम आगे भी सतत जारी रहे। बैंक लोन देने में संकोच न करें। सरकार अपनी हर योजना में ऋण दिलाने से पहले लाभार्थी का प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि जरूर सुनिश्चित करायेगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ' फैमिली आईडी' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी बैंक, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा उपलब्ध करायें। ताकि प्रदेश के हर परिवार की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा, जनधन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने वित्तीय समावेशन के प्रयासों में 'वन जीपी–वन बीसी' (एक ग्राम पंचायत–एक बीसी सखी) कार्यक्रम की सराहना करते हुए बैंकों को बीसी सखियों को और प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस एक कार्यक्रम ने महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और यह फाइनेंशियल इनक्लूजन का शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। वहीं, हालिया पेटीएम पेमेंट बैंक प्रकरण से उपजी स्थितियों से प्रभावित बीसी सखियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने पर जोर दिया। बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस व प्रशासन को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए सुचारू व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 2016–17 में प्रदेश में 12.80 लाख करोड़ का बैंकिंग बिजनेस था जो आज 26.80 लाख करोड़ के पार हो गया है। यह उत्साहजनक है। विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ौदा–यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को राज्यांश प्रदान किया, साथ ही 1.10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड , 1111 बैंकिंग आउटलेट का शुभारंभ और 10 बीसी सखियों को टूल किट वितरित किये। बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीजीएम निशा नाम्बियार की भी विशेष उपस्थिति रहीम उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स कमेटी की बैठक राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह में और जनपद में प्रत्येक माह करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एचडीएफसी बैंक द्वारा 150 वनटांगिया गाँवों को अपनाने की प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया। बैंक इन ग्रामों में 75 स्मार्ट क्लासेज का निर्माण के साथ ही ही विकास के अनेक कार्य कराएगा।

ऐसे बेहतर हुई वित्तीय स्थिति

– 2016–17 में बैंकों द्वारा प्रदेश में कुल 137452 करोड़ ऋण वितरित किया गया था। जबकि 2022–23 में कुल 300430 करोड़ का ऋण दिया गया। और दिसंबर 2023 तक 298551 करोड़ का ऋण वितरित जा चुका है।

– 07 वर्ष में 2,42,097 नए बैंकिंग आउटलेट की स्थापना।

– 07 वर्ष में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 167 लाख नए लाभार्थी जुड़े।

– 07 वर्ष में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 459 लाख नए लाभार्थी जुड़े।

– केंद्र पोषित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में यूपी नम्बर एक।

किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का आया बयान, कह दी अपने दिल की बात

छलका पीएम मोदी का दर्द

एजेंसी, नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने बीते दिन किसानों को राहत देते हुए गन्ना खरीद पर बढ़ोतरी का एतिहासिक फैसला लिया। अब इस पर पीएम मोदी का बयान आया है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''हमारी सरकार देशभर के किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना किसानों को फायदा होगा।

सरकार ने बीते दिन किसानों को राहत देते हुए गन्ना खरीद पर बढ़ोतरी का एतिहासिक फैसला लिया। अब इस पर पीएम मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार देशभर के किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

''कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाई

बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला गन्ना खरीद की कीमत में आठ फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी का था। मोदी सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस फैसले से गन्ने की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा से किसानों के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन का विस्तार

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में और संशोधन को मंजूरी भी दी। योजना में नई गतिविधियों में उद्यमिता की स्थापना शामिल है। केंद्र सरकार घोड़े, गधे और ऊंट के लिए वीर्य स्टेशन और न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये देगी।

हर जरूरतमंद और ऊर्जावान युवा को ऋण के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के यूपी सरकार के प्रयासों में बैंकों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। ऋण मेलों का यह क्रम सतत जारी रहना चाहिए।

यूपी में त्रिकोणीय हुआ लोकसभा चुनाव

सपा–कांग्रेस गठबंधन से बसपा को लगेगा बड़ा झटका

लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा–कांग्रेस में गठबंधन से प्रदेश में एनडीए से ज्यादा अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। अब त्रिकोणीय लड़ाई से मायावती के सामने पार्टी का पिछला प्रदर्शन दोहराने की ही चुनौती होगी। पिछले चुनाव में सपा–रालोद गठबंधन संग लड़ने पर बसपा को 10 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी। एक दशक पहले 'हाथी' के अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई थी। सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को थामने के लिए कांग्रेस की कोशिश रही कि विपक्षी गठबंधन में सपा–रालोद के साथ बसपा भी आ जाए लेकिन मायावती का आना तो दूर रालोद ने भी गठबंधन से नाता तोड़ लिया।

भाजपा का क्लीन स्वीप मिशन

मायावती, गठबंधन की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहती रही हैं कि पूर्व में गठबंधन करने से कांग्रेस या सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुए। ऐसे में पार्टी को लाभ न होने से अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका निर्णय 'अटल' है। इस बीच मिशन क्लीन स्वीप के लिए भाजपा जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले रालोद को वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलों को भी एनडीए में शामिल करने के साथ ही प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हुई है।

त्रिकोणीय हुआ लोकसभा चुनाव

ऐसे में यह तो साफ है कि चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। त्रिकोणीय लड़ाई होने से एनडीए को उन सीटों पर भी फायदा होने की उम्मीद है जहां खासतौर से मुस्लिम, दलित व पिछड़ों की आबादी है। सपा–कांग्रेस और बसपा में मतदाताओं के बंटने से एनडीए की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि पिछला चुनाव सपा–बसपा और रालोद के मिलकर लड़ने पर एनडीए 64 सीटों पर ही जीत सकी थी, वहीं बसपा को 10 और सपा को पांच सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर सफलता मिली थी। वर्ष 2014 के चुनाव में बसपा और सपा में गठबंधन न होने से एनडीए 73 सीटों पर कामयाब रही थी।

2019 में बसपा को पांच सीटों पर मिली थी जीत

सपा तो पांच पर जीती थी लेकिन बसपा का खाता तक नहीं खुला था। चूंकि अबकी सपा–कांग्रेस साथ है इसलिए मुस्लिम मतों का एकतरफा झुकाव उसकी ओर होने से गठबंधन को तो फायदा हो सकता है लेकिन बसपा के लिए सिर्फ दलित वोट के दम पर किसी भी सीट पर जीत सुनिश्चित करना मुश्किल दिख रहा है। वैसे भी तमाम योजनाओं के दम पर भाजपा पहले ही दलितों में काफी हद तक सेंध लगा चुकी है। अपर कास्ट के साथ ही खिसकते दलित वोट बैंक का ही नतीजा रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा 403 में से सिर्फ एक सीट पर जीती। एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय से मायावती के आगे न पलटने पर पार्टी के मौजूदा सांसद भी उनका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बसपा के 10 में से एक सुरक्षित सीट को छोड़ शेष नौ सीटों के सांसद दूसरे दलों से टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं।

लोकसभा चुनाव को लेकर सपा–कांग्रेस में गठबंधन से प्रदेश में एनडीए से ज्यादा अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। अब त्रिकोणीय लड़ाई से मायावती के सामने पाटह्न का पिछला प्रदर्शन दोहराने की ही चुनौती होगी। पिछले चुनाव में सपा–रालोद गठबंधन संग लड़ने पर बसपा को 10 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी।

देश के किसानों के लिए खुशखबरी

इस दिन अकाउंट में आ रही है पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक लाभ देना है। अभी तक सरकार ने किसानों को इस योजना के तहत 15 किस्त दे दी है। अब 28 फरवरी 2024 को किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त भी आ जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदीइस दिन देशभर के किसानों के अकाउंट में यह किस्त डीबीटी के जरिये भेजेंगे। पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 महीने के बाद किस्त के तौर पर दी जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये आते हैं।

पिछली बार सरकार ने 27 नवंबर 2024 को 15वीं किस्त जारी की थी। अब सरकार ने 16वीं किस्त जारी करने की तारीख की भी घोषणा कर दी है। सरकार ने देश के सभी किसानों के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग के किसान आसानी से उठा सके हैं।

हालांकि, योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई–केवाईसी (म्–ज्ञल्ब्) और जमीन का सत्यापन करना जरूरी है। जिन किसानों ने ई–केवाईसी और जमीन सत्यापन नहीं किया है उन्हें 16वीं किस्त के लाभ से वंचित रहना होगा। अगर आपने भी पीएम किसान स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जल्द से जल्द स्टेटस चेक करना चाहिए।

कैसे चेक करें स्टेटस

आपको पीएम किसान योजना को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद *Know Your Status*पर क्लिक करें।
अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा।
अब स्क्रीन पर शो हो रहे कैप्चा को दर्ज करें।
इसके बाद सभी जानकारी को भरें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें।
अब आपको स्क्रीन पर स्टेटस शो होगा।

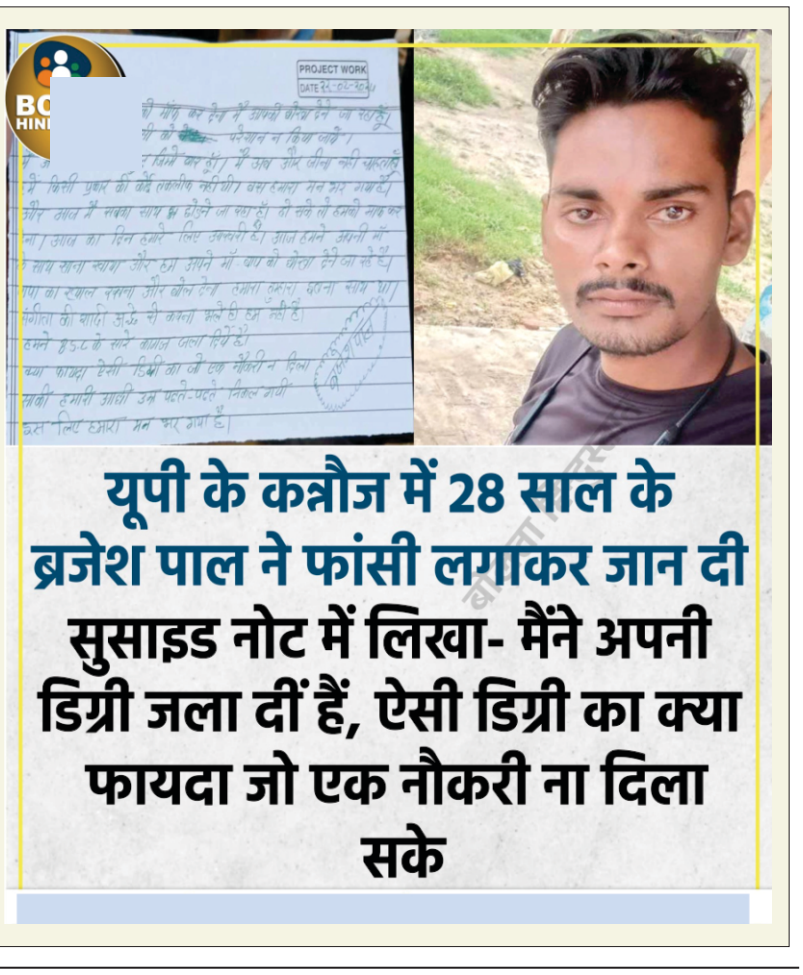

बतौर हीरो पर्दे पर रहे फ्लाप फिर भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं

रकुल के होने वाले पति का नेटवर्थ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड का फेमस कपल रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से फैंस के बीच इस कपल की शादी का जबरदस्त बज बना हुआ है। पिछले तीन दिनों से गोवा में रकुल और जैकी के प्री–वेडिंग फंक्शन का आयोजन हो रहा है। हालांकि, अभी तक इस कपल की कोई तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुई है। ऐसे में हर किसी को आज की शाम का इंतजार है, जब ये कपल अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको होने वाले दूल्हे राजा की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं।

किसके बेटे हैं जैकी भगनानी

जैकी भगनानी जाने माने प्रोड्यूसर वासु भगनानी के बेटे हैं। वासु भगनानी ने गोविंदा की फिल्म 'कुली नंबर–1' से बतौर प्रोड्यूसर काम किया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस कीं। बस फिर क्या था समय के साथ वासु ने भी अपने बेटे को हीरो बनाने का सोचा और साल 2009 में जैकी ने डेब्यू किया।

जैकी भगनानी की पहली फिल्म

साल 2009 में फिल्म 'कल किसने देखा' से जैकी भगनानी ने अपना डेब्यू किया। इस फिल्म को उनके पिता वासु भगनानी ने ही प्रोड्यूस किया था, लेकिन बेटे की पहली ही फिल्म पर्दे पर फ्लॉप रही। आखिरी बार जैकी भगनानी साल 2018 में 'मित्रों' फिल्म में दिखाई दिए थे। इस वक्त जैकी समझ गए थे की बॉलीवुड में उनका सिक्का बतौर हीरो नहीं चलने वाला, जिसके बाद उन्होंने अपनी किस्मत पिता की तरह प्रोड्यूसर बनकर आजमाई और आज वह फेमस प्रोड्यूसर की लिस्ट में शामिल है।

कितना है एक्टर का नेट वर्थ

अब जब जैकी भगनानी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन ही गए हैं। तो वह अपनी फिल्मों से करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। उनकी नेटवर्थ की तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये 35 करोड़ रुपए है। जीक्यू इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जैकी की कमाई 35 करोड़ रुपए है। जबकि एक्ट्रेस रकुल जैकी से ज्यादा कमाई करती है। रकुल की साल का 49 करोड़ कमाती हैं।

जैकी के कितनी फिल्मों में किया काम

जैकी ने पर्दे पर 9 फिल्मों में बतौर हीरो के तौर पर काम किया है। हालांकि, ये सभी फिल्मों पर्दे पर फ्लॉप रही। हालांकि जैकी बतौर बाल कलाकार 2001 में आयी फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' में भी काम कर चुके है।

दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स

मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इस साल शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी फिल्म जवान को बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला। वहा रानी मुखजीको फिल्म मिसेज चटजी वर्सेस नार्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

भारतीय क्रिकेट जगत में शोक की लहर

खिलाड़ी को पड़ा दिल का दौरा, हुई मौत

स्पोर्ट्स डेस्क। अस्पताल के डीन डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जब खिलाड़ी को अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी और पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा।

कर्नाटक के लिए खेलने वाले के. होयसला का हाल में एजिस साउथ जोन टूर्नामेंट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 34 वर्ष के थे। यह घटना बेंगलुरु के आरएसआई क्रिकेट मैदान में तमिलनाडु के खिलाफ कर्नाटक के मैच के बाद हुई। कर्नाटक की जीत का जश्न मनाने के बाद होयसला के सीने में दर्द हुआ और वह बेहोश हो गए। उन्हें एम्बुलेंस द्वारा बेंगलुरु के एक अस्पताल ले जाया जा रहा था जब उनका निधन हो गया। दिल दहला देने वाली घटना 22 फरवरी को हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी 23 फरवरी की शाम को सामने आई। होयसला मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते थे और अच्छे गेंदबाज भी थे। होयसला ने अंडर –25 वर्ग में कर्नाटक टीम का प्रतिनिधित्व किया और कर्नाटक प्रीमियर लीग का भी हिस्सा थे। अस्पताल के डीन डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जब खिलाड़ी को अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी और पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो चुका था। पोस्टमॉर्टम पूरा हो गया है और हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर से भारतीय क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी शोक जताया है और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में वह उनके परिवार के साथ हैं।

रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया के अगले कप्तान बन सकते हैं यह चार दिग्गज क्रिकेटर्स, एक तो जीत चुका है आईपीएल ट्रॉफी!

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वह ज20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत की कप्तानी करने वाले हैं. हालांकि कुछ समय बाद रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे तब टीम इंडिया को एक नए कप्तान की जरूरत होगी. आईए जानते हैं भविष्य में कौन सा खिलाड़ी भारत का कप्तान बन सकता है

लखनऊ सुपरजॉइंट कप्तान लोकेश राहुल भविष्य में टीम इंडिया का कप्तान बनने की क्षमता रखे हैं जो आईपीएल में 25 मैच जीत चुके हैं.

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी टीम इंडिया का कप्तान बन सकते हैं जो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी करते हैं. उन्होंने आईपीएल में कप्तान रहते हुए 16 मैच जीते हैं.

हार्दिक पांड्या के ज20 वर्ल्ड कप में कप्तान बनने की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. लेकिन चोटिल हो जाने के कारण वह टीम इंडिया के कप्तान बनने से रह गए . हालांकि वह भविष्य में भारत के बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं.

श्रेयस अय्यर भी भारतीय टीम के लिए कारगर कप्तान साबित सकते हैं जो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर चुके हैं.

दिल्ली कैपिटल्स को लग सकता है झटका

चोटिल हुआ यह स्टार खिलाड़ी, पिछले सीजन में कर चुका है कप्तानी

स्पोर्ट्स डेस्क। वॉर्नर को फिट होने में बस कुछ वक्त का समय लगेगा। इससे उनकी आईपीएल 2024 और वेस्टइंडीज और यूएसए में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में भागीदारी पर कोई खतरा नहीं है। आईपीएल 2024 शुरू होने में अब एक महीने से भी कम वक्त बचा है। इससे पहले ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। डेविड वॉर्नर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले चोटिल हो गए हैं। उन्हें तीसरे टी20 से पहले ग्रोइन इंजरी हुई है और वह आखिरी मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। यह वॉर्नर की आखिरी द्विपक्षीय टी20 सीरीज है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं खेलनी है और टीम सीधे जून में होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा लेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2–0 से आगे है।

वॉर्नर जल्द ठीक हो सकते हैं

हालांकि, फीजियो का कहना है कि वॉर्नर को फिट होने में बस कुछ वक्त का समय लगेगा। इससे उनकी आईपीएल 2024 और वेस्टइंडीज और यूएसए में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में भागीदारी पर कोई खतरा नहीं है। वॉर्नर दूसरे टी20 में भी नहीं खेले थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 72 रन से जीत दर्ज की। टीम अधिकारियों ने दावा किया था कि डेविड को आराम दिया गया है।

दूसरे टी20 में भी नहल खेले थे वॉर्नर

37 वर्षीय वॉर्नर दूसरे टी20 के दौरान मैदान पर दिखे थे और यहां तक कि प्री–मैच चर्चा के लिए भी दिखाई दिए थे। उन्होंने 12वें खिलाड़ी की जिम्मेदारी नहीं निभाई। सीरीज से पहले वॉर्नर ने न्यूजीलैंड के फैंस की गलत रवैये के बारे में बात की थी। पिछले बुधवार को वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में सीरीज के शुरुआती मैच में 32 रन पर आउट होने के बाद वॉर्नर की जमकर हूटिंग हुई थी। उन्होंने फैंस को फ्लाइंग किस देकर जवाब दिया था।

स्मिथ ही ओपलनग करते दिखेंगे

डेविड वॉर्नर की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ को ही ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके साथ ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम मिचेल मार्श की कप्तानी में उतरी है। ऐसा माना जा रहा है कि टी20 विश्व कप में भी टीम उन्हीं की कप्तानी में खेलती दिखेगी। हालांकि, मैट शॉर्ट भी टीम में हैं और अगले सप्ताह से शुरू होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज को देखते यह दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया अंतिम मैच के लिए किस गेम प्लान से आगे बढ़ती है। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम तीसरे टी20 में डेवोन कॉनवे के बिना उतरेगी जिन्हें दूसरे मैच में विकेटकीपिंग करते हुए अंगूठे पर चोट लगी थी।

दी नेक्स्ट पोस्ट
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003
Tital code: UPHIN51019
बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com
नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।